विज ने तोड़ी डीजीपी की नींद तो दो-दो कोठी रखने वाले आईपीएस अफ़सरों से मांगा स्पष्टीकरण

अनिल विज
गृहमंत्री

पीके अग्रवाल
डीजीपी

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पुलिस अधिकारियों के लिये आवास की भले ही कितनी कमी रहे, इसके बावजूद दर्जनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दो-दो कोठियां कब्जाये बैठे हैं। इसके लिये बहाना अतिरिक्त कार्यभार का लिया जाता है। उदाहरणार्थ कोई अधिकारी चंडीगढ या मधुबन से किसी ज़िले की तैनाती पर जाता है तो उसे नामचारे के लिये चंडीगढ़ अथवा मधुबन में कोई छोटा-मोटा अतिरिक्त कार्य-भार दे दिया जाता है। बस, इसी अतिरिक्त कार्य-भार के चलते अधिकारी अपना पुराना आवास तो खाली करते नहीं और ज़िले का नया आवास काबू कर लेते है। यह कुप्रथा न केवल आईपीएस बल्कि आईएएस अधिकारियों में भी व्याप्त है।

दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 9 साल से मंत्री पद घेरे बैठे अनिल विज को सरकारी संसाधानों की इस लूट का ज्ञान अब प्राप्त हो रहा है। यहां गौरतलब यह भी है कि अधिकारीगण केवल कोठी ही नहीं कब्जाए रहते बल्कि इन कोठियों पर सरकारी वाहन तथा ड्राइवर, लांगरी, गनमैन तथा अर्दली आदि भी रहते हैं। जाहिर है कि इस सारे लाव-लश्कर का बोझ भी सरकारी खाजाने पर ही पड़ता है।

यहां की पुलिस लाइन में अनेक वर्षों से एक कोठी पर कब्जा जमाये बैठे आईजी संजय कुमार की दीदा दिलेरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। एक ओर जहां अन्य अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार की आड़ लेकर दोहरा कब्जा जमाते हैं, वहीं संजय कुमार को इस तरह की किसी आड़ की जरूरत महसूस नहीं होती। सबसे अधिक हैरत की बात तो यह है कि यहां बतौर सीपी तैनात रहने के दौरान भी उन्होंने पुलिस लाइन वाली कोठी का कब्जा नहीं छोड़ा था। संजय एक मात्र ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो यहां 6 तैनातियां यानी कि एएसपी से लेकर आईजी तक के हर रैंक की तैनातियां काट चुके हैं और अब भी यहां की तैनाती के लिये लालायित हैं।

आईपीएस
संजय कुमार

संजय कुमार की इस कोठी एवं तैनातियों को लेकर 'मज़दूर मोर्चा' के 13-19 सितम्बर 2020 के अंक में 'आईजी संजय कुमार का पुलिस गेस्ट हाउस पर कब्ज़ा, अन्य संसाधनों का भी दुरुपयोग' शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया गया था कि संजय ने अपनी तत्कालीन हिसार रेंज में तैनाती वाली जगह से दो सरकारी गाड़ियां व अन्य पुलिस कर्मचारी यहां छोड़ रखे थे। उसी समाचार में संजय द्वारा यहां चलाये जा रहे प्रॉपर्टी डीलर के धंधे का भी विस्तृत विवरण दिया गया था।

इतना खुला खेल प्रकाशित होने के बावजूद अनिल विज समेत सारी खट्टर सरकार के कान पर जूं तक न रेंगने से समझा जा सकता है कि सरकारी संसाधनों की यह सब बर्बादी सरकार की मौन स्वीकृति से ही हो पा रही है। इस विषय में यदि सरकार की नीयत साफ है तो उसे तुरंत अवैध कब्जाधारी तमाम अफ़सरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के नाम पर कम से कम पीनल रेंट तो वसूलना ही चाहिये। परन्तु इस सरकार से ऐसा कुछ कर पाने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज को नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति नहीं

'अम्मा' को स्वीकृति प्रदान करने खट्टर खुद आये

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) केन्द्र की मोदी सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 1150 बिस्तरों का बनाया जाए तथा इसके साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाए। करीब दो साल पुरानी घोषणा के अनुरूप स्थानीय मेडिकल कॉलेज ने नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिये उस हरियाणा सरकार को आवेदन किया जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं। कॉलेज खोलने व चलाने से सम्बन्धित सारा काम-काम-काज ईएसआई कॉर्पोरेशन को ही करना है। इसके बावजूद स्वीकृति का लाइसेंस जारी करने या न करने की दादागीरी हरियाणा सरकार के पास है।

करीब आठ माह पूर्व ईएसआई मेडिकल कॉलेज ने नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिये हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था। कई माह की प्रतीक्षा के बाद अधिकारी का जवाब आया कि अभी तक सरकार ने इस बाबत कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। बड़ी अच्छी बात है, जरूरत भी क्या है जब बिना पॉलिसी के ही सारा काम चल रहा हो तो। इससे भी मजेदार बात तो यह है कि इसी शहर में स्थित 'अम्मा' के अस्पताल को नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति चाहिये थी तो उन्होंने गत माह सीएम खट्टर को अपने यहां तलब किया और स्वीकृति देने को कहा। बस फिर क्या था, पॉलिसी हो या न हो, देखते ही देखते अम्मा अस्पताल के लिये स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया।

कॉर्निया ट्रांसप्लांट की स्वीकृति में भी अड़ंगेबाजी हुई

ईएसआई मेडिकल कॉलेज लंबे समय से अपने यहां आई बैंक खोलने तथा कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने का काम शुरू करना चाहता था। इसके लिये भी हरियाणा सरकार को आवेदन किया गया। मेडिकल कॉलेज की क्षमता जांचने के लिये सरकार ने अपने उस रोहतक मेडिकल कॉलेज के निकम्मे डॉक्टरों को भेजा जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। सर्वविदित है कि वह 64 वर्ष पुराना मेडिकल कॉलेज इस नये नवेले मेडिकल कॉलेज के सामने कहीं नहीं ठहर पाता। इस तथ्य को स्वयं वहां की वाइस चांसलर डॉ. अनीता सक्सेना ने स्वीकारा है।

वहां से निरीक्षण पर आये निकम्मे डॉक्टर बेशक यहां की कार्यशैली और चकाचौंध को देखकर चुंधिया गये, लेकिन स्वीकृति के लिये अयोग्य रिपोर्ट लिख दी। इसी तरह की रिपोर्ट इन्होंने दो बार निरीक्षण करने के बाद दी। अंत में डॉ. अनीता सक्सेना ने स्वयं हस्तक्षेप करके यह स्वीकृति प्रदान की। इससे भी मजेदार बात यह है कि नहर पार खुले नये नवेले एकॉर्ड अस्पताल को यही स्वीकृति तुर्त-फुर्त प्रदान कर दी गई। अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि व्यापारिक अस्पताल तो चिकित्सा का व्यापार करके मरीजों को लूटते हैं उनके लिये सरकार के दरवाजे सदैव खुले हैं, बंद हैं तो केवल ईएसआई जैसे सार्वजनिक संस्थान के लिये।

अम्मा ने मांगी स्वीकृति, खट्टर दौड़े-दौड़े आया

नर्सिंग कॉलेज खोलने की फ़र्जी घोषणा कर गये दुष्यंत

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे नेता जब लूटने-खाने के अलावा कोई काम न कर सकें तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिये फ़र्जी घोषणाओं का सहारा लेते हैं।

इसी सप्ताह मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में अपने लगुओं-भगुओं की एक जमात को सम्बोधित करते हुए चौटाला ने अन्य कई झूठ बोलते हुए सबसे बड़ा झूठ यह बोला कि मानेसर में नर्सिंग कॉलेज खोला जायेगा। अपने झूठ को थोड़ा सा ढकने के लिये उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके लिये ईएसआई कॉर्पोरेशन का सहयोग लिया जायेगा। उन्होंने यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं समझी कि यह कॉलेज हरियाणा सरकार खोलने जा रही है या केन्द्र सरकार अथवा ईएसआई कॉर्पोरेशन? दरअसल स्पष्टीकरण तो वे तब करते न जब ऐसी कोई योजना किसी फ़ाइल तो क्या, किसी के सपने में भी होती।

हकीकत यह है कि ईएसआई कॉर्पोरेशन ने 500 बेड का अपना एक अस्पताल खोलने के लिये हरियाणा सरकार से साढे सात एकड़ ज़मीन खरीदी है। इसके लिये कॉर्पोरेशन से 120 करोड़ रुपये खट्टर सरकार ने वसूले। इतने बड़े अस्पताल के लिये यह भू-खंड बहुत ही छोटा है। भविष्य में विस्तार की किसी सम्भावना के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। विदित है कि इस क्षेत्र में 20 लाख से अधिक ईएसआई कवर्ड मज़दूरों के लिये 2,000 बेड वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सख्त जरूरत है। ऐसे में इस छोटे से भू-खंड पर चौटाला जी कैसे नर्सिंग कॉलेज बनाने का ख्वाब देख रहे हैं? कोई कॉलेज बने या न बने कहने में क्या जाता है? समझने वाली बात यह भी है कि राज्य की ईएसआई व्यवस्था को चलाने का जिम्मा श्रम मंत्री होने के नाते दुष्यंत चौटाला का ही है। इसके बावजूद राज्य द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों में डिस्पेंसरियों की दुर्दशा की तरफ झांकने का समय कभी चौटाला को नहीं मिला। यदि कोई इस संबंध में उनसे बात करने, उनको समझाने जाए भी तो झट से कह देते हैं कि उनके सेक्रेटरी से मिल लो और सेक्रेटरी उनको बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है। दरअसल चौटाला की रुचि शराब कारोबार और लोक निर्माण विभाग जैसे कमाई के धंधों में ज्यादा है। ईएसआई से तो वे केवल इतना चाहते हैं कि राज्य में बनने वाले उनके अस्पतालों व डिस्पेंसरियों के निर्माण का ठेका उन्हें दे दिया जाए। इन ठेकों के लिए उनकी जीभ लपलपा रही है।

एन्फोर्समेंट टीमों की कमाई बदस्तूर जारी

पंचकूला में बैठी ज्वाइंट कमिश्नर ने फरीदाबाद में कागजों पर लगाई दस टीमें
फरीदाबाद-मथुरा रोड पर होडल तक वाहनों की जांच नहीं करती कोई टीम

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जीएसटी चोर ट्रकों को जिले की सरहद से बिना जांच कराए निकाले जाने की काली कमाई का धंधा बदस्तूर बेखौफ जारी है। हो भी क्यों न तन्ख्वाह की रकम से कई गुना ज्यादा महीने की काली कमाई के इस धंधे में हिस्सा जो सबको पहुंचता है। हां, खुद को पाक साफ दिखाने के लिए अधिकारियों ने अब शहर में दस टीमें तो तैनात कर दीं लेकिन फरीदाबाद-मथुरा रोड को खाली रखा गया ताकि जीएसटी चोर वाहन आराम से निकल सकें।

जीएसटी चोर ट्रांसपोर्टर और एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिलीभगत हमेशा जग जाहिर रही है लेकिन एडिशनल कमिश्नर धीरज गर्ग के पकड़े जाने के साथ करोड़ों रुपये की काली कमाई वाले इस गठजोड़ का खुलासा हुआ था। इसे ट्रांसपोर्टरों, दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की सत्ता में पकड़ ही माना जाए कि विजिलेंस जांच में सब कुछ साफ होने के बावजूद केस में कोई प्रगति नहीं हो रही है। इधर, यह केस अटका हुआ है उधर, भ्रष्ट अधिकारियों-टांसपोर्टर और दलालों का खेल बदस्तूर जारी है। मज़दूर मोर्चा ने गतांक में 'जीएसटी चोरों का दलाल सरगना, वादा माफ गवाह बन गया संजीव गोस्वामी' शीर्षक से खबर छापी थी। इसमें बताया गया था कि किस तरह ट्रांसपोर्टरों का दलाल संजीव गोस्वामी अब जीएसटी चोरी वाले ट्रकों को पास कराने का सरगना बन चुका है। यह भी बताया गया था कि जिलों में एन्फोर्समेंट टीमों की ड्यूटी पंचकूला में बैठी ज्वाइंट कमिश्नर कुमुद लगाती हैं और वह फरीदाबाद में टीमों की ड्यूटी नहीं लगातीं।

खबर छपने का असर यह हुआ कि कुमुद सिंह ने फरीदाबाद के लिए 21 से 23 जून के लिए दस टीमें लगाईं लेकिन इन्हें तीन अन्य जिलों का भी प्रभार दे दिया गया। गुड़गांव के एन्फोर्समेंट अधिकारी रंजीत सिंह, सत्यवीर, अभिषेक सांगवान और पुष्पेंद्र, फरीदाबाद के एईटीओ विकास, सुब्रत शर्मा, ललित यादव, सोनीपत के एईटीओ वीरेंद्र दलाल और अंबाला के एईटीओ की टीम को कागजों में फरीदाबाद की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ ही सभी को पलवल, मेवात और गुड़गांव में भी जांच का जिम्मा सौंपा गया।

21 की रात एक टीम लगी भी उसने एक दो ट्रकों को रोका तो बात ट्रांसपोर्टरों के जरिए दलालों के सरगना और वहां से अधिकारियों तक पहुंची। बस फिर क्या था रोज की तरह फरीदाबाद-मथुरा रोड को होडल की सीमा तक खाली छोड़ दिया गया। कार्रवाई दिखाने के लिए इन टीमों ने उन्हीं ट्रकों को पकड़ा जिनका नाम सूची में नहीं था। दूसरी रात इन सभी टीमों की ड्यूटी गुड़गांव, मेवात में लग गई। वर्तमान में फरीदाबाद-मथुरा रोड जीएसटी चोर गैंग के ट्रकों के लिए खुला हुआ है। बताते चलें कि विजिलेंस को धीरज गर्ग, देवेंद्र सिंह, संजीव गोस्वामी ने जांच के दौरान अमन ट्रांसपोर्ट, विजय भारत रोड लाइंस, लाइन ट्रांसपोर्ट, हरियाणा मेवात ट्रांसपोर्ट के साथ ही न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम बताए थे जिनके ट्रक निकाले जाने की एवज में लाखों रुपये रिश्वत दी जाती थी। आबकारी एवं कराधान विभाग के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार जीएसटी चोरी की काली कमाई का लेन देन सेक्टर नौ स्थित पूर्व डीटीसी रविंद्र सिंह की कोठी पर आज भी होता है यानी संजीव गोस्वामी और उसके जैसे दलालों से वसूली और उसका हिस्सा ऊपर तक पहुंचाने में इस कोठी की भी अहम भूमिका है।

जीएसटी चोरी तभी रोकी जा सकती है जब बदरपुर बॉर्डर पर ईमानदार अफसरों की टीम तैनात रहे। यह तब ही मुमकिन हो जब सरकार भी ईमानदारी से जीएसटी चोरी रोकने को गंभीर हो।